रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 28 जून, 1985/7 आषाढ़, 1907

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171004, 28 जून, 1985

संख्या 1-43/85-वि०स०—हिमाचल प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 1973 के नियम 135 के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1985 (1985का विधेयक संख्यांक 3)

1336-राजपत्र/85-28-6-85—1,157.

मूल्य: 20 पैसे।

जो दिनांक 28 जून, 1985 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो गया है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

विश्वेश्वर वर्मा,
सचिव ।

1985 का विधेयक संख्यांक 3.

हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1985

(विधान सभा में यथा पारित)

वित्तीय वर्ष 1985-86 के कुछ भाग के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय धनराशियां निकालने का उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1985 है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए 55,14,85,000 रुपये निकालना ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट से अनधिक धनराशियां, जिनका योग पचपन करोड़, चौदह लाख, पचासी हजार रुपये है, वित्तीय वर्ष 1985-86 के जुलाई मास में अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित संदायों के विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिये, निकाली जाएं ।

विनियोग ।

3. इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से निकाली जाने के लिये प्राधिकृत धनराशियों का विनियोग अधिनियम की धारा 2 में उल्लिखित अवधि के सम्बन्ध में अभिव्यक्त प्रयोजनों और सेवाओं के लिये किया जायेगा ।

अनुसूची

(धारा 2 तथा 3 देखिए)

मांग संख्या	सेवाएं तथा प्रयोजन		निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
			विधान सभा द्वारा दत्तमत	संचित निधि पर प्रभारित	जोड़
1	2		3		4
			रुपये	रुपये	रुपये
1	विधान सभा तथा निर्वाचन	(राजस्व)	10,52,000	14,000	10,66,000
2	राज्यपाल तथा मन्त्री परिषद्	(राजस्व)	4,19,000	1,75,000	5,94,000
3	न्याय प्रशासन	(राजस्व)	15,87,000	4,86,000	20,73,000
4	सामान्य प्रशासन	(राजस्व)	88,88,000	2,34,000	91,22,000
		(पूंजी)	24,000	—	24,000
5	भू-राजस्व	(राजस्व)	60,71,000	—	60,71,000
		(पूंजी)	75,000	—	75,000
6	आबकारी तथा कराधान	(राजस्व)	19,72,000	—	19,72,000
7	पुलिस तथा अग्नि सुरक्षा	(राजस्व)	1,32,15,000	—	1,32,15,000
8	शिक्षा, कला तथा संस्कृति एवं वैज्ञानिक अनुसंधान ।	(राजस्व)	5,95,65,000	—	5,95,65,000
		(पूंजी)	10,36,000	—	10,36,000
9	चिकित्सा और परिवार नियोजन	(राजस्व)	2,03,98,000	—	2,03,98,000
		(पूंजी)	21,89,000	—	21,98,000
10	लोक निर्माण	(राजस्व)	2,90,53,000	—	2,90,53,000
		(पूंजी)	20,29,000	—	20,29,000
11	कृषि	(राजस्व)	1,62,85,000	—	1,62,85,000
		(पूंजी)	62,07,000	—	60,07,000
12	लघु सिंचाई	(राजस्व)	90,65,000	—	90,65,000
		(पूंजी)	21,87,000	—	21,87,000
13	भूमि तथा जल संरक्षण	(राजस्व)	56,01,000	—	56,10,000
		(पूंजी)	2,90,000	—	2,90,000
14	पशुपालन तथा दुग्ध विकास	(राजस्व)	52,48,000	2,000	52,50,000
		(पूंजी)	6,84,000	—	6,84,000
15	मत्स्य	(राजस्व)	5,00,000	—	5,00,000
		(पूंजी)	2,77,000	—	2,77,000
16	वन	(राजस्व)	1,60,20,000	—	1,60,20,000
		(पूंजी)	11,68,000	—	11,68,000
17	सड़कें तथा पुल	(राजस्व)	93,66,000	—	93,66,000
		(पूंजी)	2,37,58,000	22,000	2,37,80,000
18	सप्लाई, उद्योग तथा खनिज	(राजस्व)	85,05,000	—	85,05,000
		(पूंजी)	16,72,000	—	16,72,000

1	2		3		4
			रुपये	रुपये	रुपये
19	सामाजिक सुरक्षा कल्याण तथा जेल।	(राजस्व)	78,39,000	—	78,39,000
		(पूंजी)	4,95,000	—	4,95,000
20	लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं जल आपूर्ति	(राजस्व)	2,46,68,000	—	2,46,68,000
		(पूंजी)	91,60,000	—	91,60,000
21	सामुदायिक विकास	(राजस्व)	1,69,90,000	2,000	1,69,92,000
		(पूंजी)	32,000	—	32,000
22	सहकारिता	(राजस्व)	31,19,000	—	31,19,000
		(पूंजी)	31,64,000	—	31,64,000
23	खाद्य एवं पोषाहार	(राजस्व)	29,61,000	—	29,61,000
		(पूंजी)	72,96,000	—	72,96,000
24	जल तथा विद्युत विकास	(राजस्व)	14,33,000	—	14,33,000
		(पूंजी)	3,59,34,000	—	3,59,34,000
25	सिंचाई, नावचालन, जल निकास तथा बाढ़ नियन्त्रण।	(राजस्व)	14,16,000	—	14,16,000
		(पूंजी)	17,89,000	—	17,89,000
26	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	(राजस्व)	18,30,000	—	18,30,000
		(पूंजी)	4,58,000	—	4,58,000
27	सड़क परिवहन	(राजस्व)	2,48,000	—	2,48,000
		(पूंजी)	16,01,000	—	16,01,000
28	पर्यटन	(राजस्व)	3,07,000	—	3,07,000
		(पूंजी)	4,64,000	—	4,64,000
29	श्रम तथा रोजगार	(राजस्व)	14,08,000	—	14,08,000
		(पूंजी)	88,000	—	88,000
30	आवास	(राजस्व)	6,77,000	—	6,77,000
		(पूंजी)	13,14,000	—	13,14,000
31	नगर विकास	(राजस्व)	33,03,000	—	33,03,000
		(पूंजी)	5,29,000	—	5,29,000
32	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	(राजस्व)	95,68,000	—	95,68,000
		(पूंजी)	6,65,000	—	6,65,000
33	वित्त	(राजस्व)	1,06,09,000	2,89,16,000	3,95,25,000
		(पूंजी)	—	8,52,37,000	8,52,37,000
34	सरकारी कर्मचारियों को ऋण।	(पूंजी)	26,58,000	—	26,58,000
35	जनजातीय विकास	(राजस्व)	2,13,83,000	—	2,13,83,000
		(पूंजी)	85,85,000	—	85,85,000
		जोड़ ..	43,63,97,000	11,50,88,000	55,14,85,000

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 203 और 204 के अधीन विहित प्रक्रिया के पूर्ण होने तक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 206 के अध्ययन सहित अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1985-86 के जुलाई मास के लिए अपेक्षित धन के ऐसे व्यय को जो संचित निधि पर प्रभारित है और विधान सभा द्वारा यथा दत्तमत अन्य व्यय को पूरा करने के लिए, निकालने का उपबन्ध करने के लिए पुरःस्थापित है । मांगे गये धन में वर्ष 1985-86 की वस्तुतः नई स्कीमों का प्रावधान सम्मिलित नहीं है ।

सरकार ने 1985 के विधेयक संख्यांक 2 द्वारा संचित निधि पर प्रभारित व्ययों और विधान सभा द्वारा यथा दत्तमत व्ययों को पूरा करने के लिये मार्च, 1985 में तीन मास के लिये दत्तमत लेखा अनुदान अभिप्राप्त किया था । नियमित बजट विधान सभा द्वारा जुलाई, 1985 में पारित किया जाना है । अतः जुलाई, 1985 के लिए लेखा अनुदान अभिप्राप्त करना है ।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री ।

शिमला :
28 जून, 1985

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 207 के अन्तर्गत राज्यपाल की सिफारिशें ।

[वित्त विभाग फाईल संख्या फिन-ए-सी-(1) 26/84-II]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1985 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारतीय संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और विचार करने की सिफारिश करते हैं ।

[*Authorised English Text of the Himachal Pradesh Viniyog (Lekha Anudan) Vidheyak*, (1985 *Bill No.* 3 *of* 1985) *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

Bill No. 3 of 1985.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 1985

(AS PASSED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services of a part of the financial year 1985-86.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the State of Himachal Pradesh in the Thirty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1985.

Withdrawal of Rs. 55,14,85,000 from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 1985-86.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh there may be withdrawn sums not exceeding those specified in column 3 of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of fifty-five crores, fourteen lakh and eighty-five thousand rupees towards defraying several charges which will come in course of payment during the month of July of the financial year 1985-86 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be withdrawn from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the period mentioned in section 2 of the Act.

THE SCHEDULE

(*See* section 2 and 3)

Demand No.	Services and purposes		Sums not exceeding		Total
			Voted by Legislative Assembly	*Charged* on the Consolidated Fund	
1	2		3		4
			Rs.	Rs.	Rs.
1	Vidhan Sabha and Elections	(Revenue)	10,52,000	14,000	10,66,000
2	Governor and Council of Ministers	(Revenue)	4,19,000	1,75,000	5,94,000
3	Administration of Justice	(Revenue)	15,87,000	4,86,000	20,73,000
4	General Administration	(Revenue)	88,88,000	2,34,000	91,22,000
		(Capital)	24,000	—	24,000
5	Land Revenue	(Revenue)	60,71,000	—	60,71,000
		(Capital)	75,000	—	75,000
6	Excise and Taxation	(Revenue)	19,72,000	—	19,72,000
7	Police and Fire Protection	(Revenue)	1,32,15,000	—	1,32,15,000
8	Education, Art and Cultural Affairs and Scientific Research	(Revenue)	5,95,65,000	—	5,95,65,000
		(Capital)	10,36,000	—	10,36,000
9	Medical and Family Planning	(Revenue)	2,03,98,000	—	2,03,98,000
		(Capital)	21,89,000	—	21,89,000
10	Public Works	(Revenue)	2,90,53,000	—	2,90,53,000
		(Capital)	20,29,000	—	20,29,000
11	Agriculture	(Revenue)	1,62,85,000	—	1,62,85,000
		(Capital)	62,07,000	—	62,07,000
12	Minor Irrigation	(Revenue)	90,65,000	—	90,65,000
		(Capital)	21,87,000	—	21,87,000
13	Soil and Water Conservation	(Revenue)	56,01,000	—	56,01,000
		(Capital)	2,90,000	—	2,90,000
14	Animal Husbandry and Dairy Development.	(Revenue)	52,48,000	2,000	52,50,000
		(Capital)	6,84,000	—	6,84,000
15	Fisheries	(Revenue)	5,00,000	—	5,00,000
		(Capital)	2,77,000	—	2,77,000
16	Forests	(Revenue)	1,60,20,000	—	1,60,20,000
		(Capital)	11,68,000	—	11,68,000
17	Roads and Bridges	(Revenue)	93,66,000	—	93,66,000
		(Capital)	2,37,58,000	22,000	2,37.80,000
18	Supplies, Industries and Minerals	(Revenue)	85,05,000	—	85,05,000
		(Capital)	16,72,000	—	16,72,000
19	Social Security, Welfare and Jails	(Revenue)	78,39,000	—	78,39,000
		(Capital)	4,95,000	—	4,95,000
20	Public Health, Sanitation and Water Supply.	(Revenue)	2,46,68,000	—	2,46,68,000
		(Capital)	91,60,000	—	91,60,000
21	Community Development	(Revenue)	1,69,90,000	2,000	1,69,92,000
		(Capital)	32,000	—	32,000
22	Co-operation	(Revenue)	31,19,000	—	31,19,000
		(Capital)	31,64,000	—	31,64,000
23	Food and Nutrition	(Revenue)	29,61,000	—	29,61,000
		(Capital)	72,96,000	—	72,96,000
24	Water and Power Develoment	(Revenue)	14,33,000	—	14,33,000
		(Capital)	3,59,34,000	—	3,59,34,000

1	2		3		4
			Rs.	Rs.	Rs.
25	Irrigation, Navigation, Drainage and Flood Control.	(Revenue)	14,16,000	—	14,16,000
		(Capital)	17,89,000	—	17,89,000
26	Stationery and Printing	(Revenue)	18,30,000	—	18,30,000
		(Capital)	4,58,000	—	4,58,000
27	Road Transport	(Revenue)	2,48,000	—	2,48,000
		(Capital)	16,01,000	—	16,01,000
28	Tourism	(Revenue)	3,07,000	—	3,07,000
		(Capital)	4,64,000	—	4,64,000
29	Labour and Employment	(Revenue)	14,08,000	—	14,08,000
		(Capital)	88,000	—	88,000
30	Housing	(Revenue)	6,77,000	—	6,77,000
		(Capital)	13,14,000	—	13,14,000
31	Urban Development	(Revenue)	33,03,000	—	33,03,000
		(Capital)	5,29,000	—	5,29,000
32	Other Administrative Services	(Revenue)	95,68,000	—	95,68,000
		(Capital)	6,65,000	—	6,65,000
33	Finance	(Revenue)	1,06,09,000	2,89,16,000	3,95,25,000
		(Capital)	—	8,52,37,000	8,52,37,000
	oans to Government Servants	(Capital)	26,58,000	—	26,58,000
35	Tribal Development	(Revenue)	2,13,83,000	—	2,13,83,000
		(Capital)	85,85,000	—	85,85,000
		Total ...	43,63,97,000	11,50,88,000	55,14,85,000

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of Article 204 read with Article 206 of the Constitution of India to provide for withdrawal from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and other expenditure as voted by the Legislative Assembly for the month of July, 1985 of the financial year 1985-86 pending the completion of the procedure prescribed in Article 203 and 204 of the Constitution of India. The moneys demanded do not include the provision for the Really New Schemes for the year 1985-86.

The Government obtained three months Vote on Account *vide* Act No. 2 of 1985 to meet the expenditure on the Consolidated Fund and other expenditure as voted by the Legislative Assembly in March, 1985. The regular Budget is to be passed by the Legislative Assembly in July, 1985. As such the Vote on Account is being obtained for July, 1985.

SHIMLA :
The 28th June, 1985.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[Finance Department File No. Fin.A.C (1) 26/84-II]

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the proposed Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Bill, 1985, recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction in, and consideration by, the Legislative Assembly of the said Bill.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।

रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 29 जून, 1985/8 आषाढ़, 1907

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-171004, 29 जून, 1985

क्रमांक एल० एल० आर०-डी० (6) 15/85.—हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1985 (1985 का संख्यांक 3) जैसा राज्यपाल महोदय द्वारा "भारत के संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत

1353-राजपत्र/85-29-6-85—1,192. मूल्य: 20 पैसे।